सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-237 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, गुरूवार 01 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी; कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली । जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ-साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुल संख्या का पता चल सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का एलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, %राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसेक बाद एक मंत्रीमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की संस्तुति की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन

के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण सुचारू रूप से किया है, जबकि राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में भ्रांति फैली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा सामाजिक ताना-बाना राजनीति के दबाव में न आए। हमें जाति जनगणना के लिए एक मंच तैयार करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और समाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश का विकास भी निर्बाध रूप से चलती रहेगी।

प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है जनगणना

जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर एलान भी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जाएंगे। इससे भविष्य में जनगणना का चक्र बदल जाएगा। जैसे 2025-2035 और फिर 2035 से 2045।

क्यों अहम है जनगणना?

जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ-साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति कई अहम पहलुओं का पता चलता है। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुल संख्या का पता चल सके। भारत में हर दस साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 74.04 फीसदी था।

जयश्री मीणा ने संभाला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाकसू का कार्यभार

मीनेश चन्द्र मीना, हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

चाकसू। जयपुर जिले के चाकसू स्थित सिविल एवं फौजदारी न्यायालय में बुधवार को जयश्री मीणा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-19 के पद पर कार्यभार संभाला।

गौर तलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण की लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट के मुताबिक जयश्री मीणा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-19 के पद पर स्थानांतरण किया था।

इस प्रकार स्थानांतरण होने के बाद जय श्री मीणा ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा और महासचिव दुर्गा प्रसाद बैरवा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट का पारंपरिक स्वागत किया। उन्होंने जयश्री मीणा को साफा पहनाया और पुष्पगुच्छ के साथ स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। इनमें कोषाध्यक्ष किशन प्रजापत, पूर्व अध्यक्ष हरप्रीत सिंह, पूर्व महासचिव श्रवण लाल शर्मा शामिल थे। अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा, जीतेंद्र गौतम, मुकेश कुमार मामोडिया, राजेश चौधरी, सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीणा ने कहा कि वे बार और बेंच के बीच समन्वय बनाकर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करेंगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष एन.एल. शर्मा ने न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

गहलोत ने पंचायतों के परिसीमन में धांधली का लगाया आरोप

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर इस प्रक्रिया में मनमानी और संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार और नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि परिसीमन और पुनर्गठन नियमानुसार और जनहित में किया गया है।

नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है।

राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम-कानून तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछज्

उन्होंने कहा कि भाजपा और ऋस्र मिलकर येन-केन-प्रकरेण पंचायतीराज और नगरीय निकाय के चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए पहले भरतपुर जिला प्रमुख समेत कई जगह इनके उपचुनाव तक नहीं करवाए। फिर वन स्टेट-वन इलेक्शन के नाम पर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए एवं अब ये वोटबैंक को साधकर जीतने के लिए नियमों एवं जनता की सहूलियत को भी अनदेखा कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि न तो न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या के पैमाने को माना जा रहा है और न ही मुख्यालय से उचित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। कहीं शहर से 10-10 किलोमीटर दूर के गांवों को नगरीय निकायों में मिलाया जा रहा है तो कहीं गांवों को इस तरह पंचायतों से जोड़ा जा रहा है कि पंचायत मुख्यालय ही 5 से 10 किलोमीटर दूर हो गया है।

जनता में आक्रोश, कलेक्टरों पर दबाव

गहलोत ने कहा कि मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियां उचित नहीं है। जनता में इसको लेकर आक्रोश पनप रहा है। जिला कलेक्टरों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दबाव में न आकर नियमानुसार सुसंगत तरीके से पूरी पुनर्गठन प्रक्रिया हो।

राजनीतिक लाभ की कोशिश- विपक्ष

बताते चलें कि विपक्षी नेताओं का शुरू से ही इस प्रक्रिया पर आरोप है कि परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए हथियार बना रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कवायद वोटबैंक को मजबूत करने और चुनावी जीत सुनिश्चित करने की साजिश है।

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन समिति के सदस्यों पर सत्तारूढ़ दल का दबाव है, जिसके चलते जनता की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और मुख्यालय बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

सांसद मदन राठौड़ बोले- जातिगत जनगणना से नहीं आएगा आर्थिक बोझ, कांग्रेस और गहलोत पर साधा निशाना

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने जातिगत जनगणना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के कथित पोस्टर और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा किए गए पुनर्गठन पर अपनी बात रखी।

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार का सामान्य जनगणना के साथ ही जाति का एक कॉलम जोड़ने का निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे देश पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर पहले अलग से जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मांग गलत समय पर की गई थी और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना था, जिससे देश पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता।

राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री का सिर गायब वाला पोस्टर जारी करने की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री को सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रही है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, बल्कि देश के हैं और आतंकवाद के खिलाफ उनके कड़े फैसलों का पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेसी नेता धृतराष्ट्र बने हुए हैं और उन्हें यह नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इसे कांग्रेस के दिमाग की शून्यता और राजनीतिक गिरावट बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत ने अपनी अल्पमत सरकार बचाने के लिए विधायकों को खुश करने हेतु रेवड़ियों की तरह पद बांटे और पंचायतों व नगरीय निकायों का अव्यवस्थित पुनर्गठन किया, जिसमें मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता थी।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार नियमों के अनुसार समान जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित पुनर्गठन कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और गहलोत अपनी पिछली सरकार की कमियों को भाजपा सरकार पर थोपना चाहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन

जयपुर,। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के दौरान राज्य स्तर पर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठनअंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन कृषि एवं उद्यानिकी तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सार्वजनिक

वितरण एवं उपभोक्ता मामले, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्रीगण इस समिति के सदस्य बनाएं गये हैं। मुख्य सचिव को समिति का सदस्य संयोजक तथा वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिवों को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जनसम्पर्क , राजस्व एवं उपनिवेशन , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और सहकारिता विभागों के प्रमुख शासन सचिव व मत्स्य, पशुपालन और डेयरी और कृषि और बागवानी विभाग के शासन सचिव भी सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

साइबर हमले के बाद राजस्थान ने त्वरित कार्यवाही शुरू की, दुर्भावनापूर्ण कोड हटाया

जयपुर। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और शहरी विकास एवं आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट्स, जो राज्य डेटा सेंटर पर होस्ट की गई थीं, 28 अप्रैल, 2025 की रात लगभग 10ञ्54 बजे साइबर हमले का शिकार हुईं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस हैकिंग के पीछे एक दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस की सक्रिय भूमिका थी। राहत की बात है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की डेटा हानि नहीं हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार विभाग ने इस साइबर हमले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। साथ ही प्रभावित वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है

और आगे के नुकसान को रोकने के विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही, वेबसाइट्स से दुर्भावनापूर्ण कोड को हटा दिया गया है और उन्हें सुरक्षा ऑडिट के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, पहचाने गए दुर्भावनापूर्ण आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है। इन कदमों के साथ ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ष्टश्वक्रञ्ज-ढ्ढठ्ठ (कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) को मामले की गहन जांच के लिए शामिल किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट पूर्ण होने के बाद प्रभावित वेबसाइट्स को 30 अप्रैल, 2025 तक पुन: सक्रिय कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार इस घटना की गंभीरता को समझते हुए डिजिटल सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया - अमित शाह

नई दिल्ली,। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा है कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।

शाह ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा, ऋप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी सम्मिलित कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये निर्णय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई

जातियों को मुख्य धारा में लाने तथा लंबे समय से अपने हक और अधिकार से अछूते लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने लंबे समय तक जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने तथा उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण है कि स्वतंत्रता के बाद देश में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का यह अभूतपूर्व निर्णय सामाजिक समरसता के विस्तार के साथ ही हर वर्ग के उत्थान एवं पिछड़े तबके के सम्मान को बढ़ाने में मील का पत्थर बनेगा। सर्व समाज के कल्याण करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

श्रमिक दिवस पर जिले में रहेगा सवैतनिक अवकाश

टोंक। आगामी गुरुवार को श्रमिक दिवस के अवसर पर जिले में सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य नियोजकों को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश सहायक श्रम आयुक्त कमल सिंह चांदोलिया ने जारी किया है।

श्रम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्रमिक दिवस का आयोजन सद्भावना और सम्मान के साथ किया जाएगा। यह दिन श्रमिकों के अधिकार, योगदान और सम्मान को समर्पित है।

मजदूरों के हितों को सुरक्षित करना होगा तभी मजदूर दिवस की सार्थकता होगी?

भारतीय दंड सहिंता की धारा 304 के अंर्तगत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।यह मजदूर बिहार के समस्तीपुर के एक ही गांव के है।पलक झपकते ही अनाज मंडी शमशानघाट बन गई थी ।लाशों के ढेर लग गए थे ।चीखो पुकार मच गई थी ।मजदूर खाक ह गए थे । कैसी विडंबना है कि कभी सुरगों व उद्योगों में बेमौत मारे जा रहे हैं। मगर केन्द्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है।2025 के 4 महिनों में उद्योगों में आग के काफी मामले घटित हुए है। देश में मजदूरों के साथ होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

(लेखक- नरेन्द्र भारती /)

(1 मई 2025 मजदूर दिवस पर विशेष)

बेशक देश में प्रतिवर्ष की तरह 1 मई को मजदूर 2025 दिवस मनाया जा रहा है। केवल मात्र एक दिन बड़े-बड़े सैमिनार,गोष्ठियां की जाती है मजदूरों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बड़े दावे किये जातें है मगर 364 दिन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता कि मजदूरों के साथ कैसे-कैसे हादसे होते रहते है ।प्रतिदिन समाचार पत्रों में मजदूरों के मरने की खबरें सुखियां बनती है मगर सरकारें मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही हैं। देश के कारखानों में मजदूर मर रहे हैं हर जगह मजदूर काल का ग्रास बन रहे है। देश में मजदूरों के साथ हादसे कब थमेगें यह एक यक्ष प्रशन है। हर साल दिवस मनाए जाते है मगर धरातल की सच्चाइयां बहुत ही भयानक है मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूरों के नाम पर सैकडों योजनाए चलाई जाती है मगर उन्हे उनका हक नहीं मिलता। देश में हर रोज मजदूर बेमौत मर रहे हैं ।प्रतिदिन समाचार पत्रों में मजदूरों के मरने की खबरें सुखियां बनती है मगर सरकारें मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही हैं। देश में मजदूरों के साथ हादसे थमने का नाम नहीं ले रहें हैं ।हर साल दिवस मनाए जाते है मगर धरातल की सच्चाइयां बहुत ही भयानक है मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूरों के साथ होने वाले यह हादसे बहुत ही त्रासदी है ।कहीं उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं ।हादसों की बजह से बच्चे अनाथ हो रहे है ।मगर केन्द्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है। देश में हर वर्ष लाखों मजदूर दबकर मारे जा रहे हैं उद्योगों में जलकर मारे जा रहे हैं। मगर केन्द्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है ।देश के कारखानों में मजदूर मर रहे हैं, इमारतों के नीचे दबकर मजदूर काल का ग्रास बन रहे है ।हादसों को देखकर रौगंटे खड़े हो जाते हैं देश के राज्यों में चल रहे ईटों के भठठों में मजदूर मारे जा रहे हैं ।मजदूरों के पसीने से ही ईटें पकती हैं मगर भठठा मालिक मजदूरों का शोषण कर रहे हैं मजदूर खून-पसीना बहाकर काम करते है ।मगर बदले में मेहनताना नाममात्र दिया जाता है ।मालिक मजदूरों के सिर पर करोड़ों रुपया कमा रहे है ।आकडों के मुताबिक बीते सालों में देश में हजारों मजदूर मारे जा चुके है ।हादसों नं सवाल खड़े कर दिये हैं कि बार-बार हो रहे इन हादसों के कारण क्या है इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बीती घटनाओं से न तो सरकार ने सबक सिखा और न ही लोगों ने सीखा। हांलाकि इसयह कोई पहला हादसा नहीं है पिछले कई सालों से ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। फ़रवरी 2024 को बद्दी की परफ्यूम फैक्ट्री में घटित हुआ जहाँ 35 लोग झुलस गए और एक महिला की मौत हो गई चार लोगों को पीजआई में भर्ती किया है द्य अभी भी 20 लोग लापता हैं सर्च ऑपरेशन जारी है फैक्ट्री के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है आगजनी के समय करीब 50 कामगार मौजूद थे 30 कामगारों ने ऊपरी मंजिल से कूद कर अपनी जान बचा ली इनमे तीन की रीढ़ की हड्डी टूट गई मलिक पर लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है इससे पहले भी बद्दी में काफ़ी अग्निकांड हो चुके हैं लेकिन सबक नहीं सीख रहे हैं सरकारों को इस हादसे से संज्ञान लेना चाहिए .2019 में राजधानी दिल्ली में रानी झांसी रोड़ पर स्थित अनाज मंडी में रविवार सुबह चार बजे आग लगने से 43 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे ।एडीआरएफ की टीम ने केवल 56 लोगों की जान बचा ली थी ।यह भीषण आग सुबह साढे चार बजे के करीब लगी थी ।आग लगने का कारण शार्टसर्किट था । भारतीय दंड सहिंता की धारा 304 के अंर्तगत मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है ।यह मजदूर बिहार के समस्तीपुर के एक ही गांव के है ।पलक झपकते ही अनाज मंडी शमशानघाट बन गई थी ।लाशों के ढेर लग गए थे ।चीखो पुकार मच गई थी ।मजदूर खाक ह गए थे । कैसी विडंबना है कि कभी सुरगों व उद्योगों में बेमौत मारे जा रहे हैं। मगर केन्द्र व राज्य की सरकारों को जरा सा सदमा होता तो मजदूरों के हितों में कदम उठाती लेकिन सरकारें तो तब जागती हैं जब बड़ा हादसा घटित हो जाता है ।2025 के 4 महिनों में उद्योगों में आग के काफी मामले घटित हुए है। देश में मजदूरों के साथ होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ।कारखानों में जल कर मजदूर मर रहे हैं ।गत वर्ष भी एक ही दिन में दो हादसों में 19 मजदूर मारें गए थे जब राजधानी दिल्ली के बाहरी जिले में स्थित बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक पटाखें की फैक्टरी के गोदाम में भीषण आग लगनें के कारण 17 लोगों की मौत हो गई थी और तीस लोग बुरी तरह झुलस गए थे। मरने वालों में 10 महिलाएं तथा 7 पुरुष थी ।मजदूरों ने सपने में भी नही सोचा होगा कि यह पटाखा गोदाम शमशान बन जाएगा ।पल भर में जिन्दा लोग राख में बदल गए यह बहुत ही त्रासदी है ।लगभग तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका तब तक सब कुछ राख हो चुका था ।आग के कारणो का पता नहीं चल पाया है ।प्रशासन को चाहिए कि लापरवाही बरतने वालों को सजा दी जाए ताकि फिर एसे हादसे न हो सके ।दूसरे हादसे में कानपुर में भी दो मजदूरों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक दिन में ही 19 मजदूर मारे गए ।यह बहुत ही दुखद है। ।बीते वर्ष में रायबरेली के उंचाहार में एटीपीसी संयत्र का बायलर फटने से 30 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी तथा 100के लगभग घायल हो गए थे ।500 मैगावाट इकाई के बायलर में यह हादसा हुआ था उस समय 200 कामगार मौजूद थे सरकारों ने मृतकों को मुआवजे की घोषणा करती है मगर मुआवजा इसका हल नहीं है ।एक ऐसा ही हादसा जयपुर के पास खातोलाई गांव में घटित हुआ था जहां टाऊनफारमर फटने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इन हादसों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा पर प्रशनचिन्ह लगा दिया है इन हादसों पर संज्ञान लेना होगा तथा मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होगें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके। गत वर्ष जम्मू के उधमपूर से 80 किलोमीटर दूर रामबन जिले के चंद्रकोट में जम्मू-कश्मीर हाईवे पर टनल कर्मचारियों की बैरक में आग लगने से दस श्रमिक जिंदा जल गए थे। यह बैरक लोहे व फाईबर की बनी थी। यह बहुत ही दुखद हादसा था। आग लगने का कारण बिजली का शार्टसर्किट था ।इस बैरक में 100 से अधिक लोग रहते थे। मगर छुटटी होने के कारण आसपास के लोग अपने घरों को चले गए थे। गनीमत रही की यह अपने-अपने घरों को गए थे वरना मृतको की संख्या 100 के लगभग होती ।नया वर्ष इन मजदूरों के लिए यमराज बन कर आया था और बेचारे टनल में ही जिन्दा जलकर राख हो गए थे इन अभागों ने सपने मे भी नहीं सोचा होगा की नया साल उनके लिए घातक साबित होगा ।मारे गए मजदूरों में एक मजदूर हिमाचल के कांगड़ा का था तथा एक पंजाब का था बाकि बनिहाल-रामबन क्षेत्र के निवासी थे ।सुरगं में घटित इस दर्दनाक हादसे ने कई प्रशन खड़े कर दिए है कि आखिर यह हादसे कब रुकेगें ।यह कोई पहला हादसा नहीं है देश में अब तक हजारों मजदूर बेमौत मारे जा चुके है ।एक साल पहले हिमाचल के बिलासपुर में भी एक ऐसा ही हादसा घटित हुआ था जब फोरलेन का काम करते समय सुरंग ढह गई और तीन मजदूर उसमें दब गए मगर 12 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दो मजदूरों को जिन्दा निकाला गया था। एक मजदूर हिरदा राम कोई पता नहीं चल पाया था कि वह जिन्दा था या मर चुका था लगभग 9 महीने बाद उसका शव बरामद हुआ था। हिमाचल के जिला किन्नौर में एक निर्माणाधिन प्रोजेक्ट की दीवार गिरने से चार मजदूर बेमौत मारे गए थे। यहां पर 11 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई सात मजदूर तो भागकर बच गए मगर बेचारे चार मजदूर जिन्दा दफन हो गए ।इन मजदूरों पर 42 मीटर लंबी दीवार गिर गई थी। हिमाचल में ऐसे बहुत हादसे हो रहे है हमीरपुर में भी गत दिनों दर्जनों मजदूर मारे गए थे। 2015 के फरवरी माह में एक सप्ताह में दो दर्दनाक हादसों में 10 मजदूर मारे गए और 20 मजदूर घायल हो गए। पहला हादसा हिमाचल के कुल्लु में हुआ तथा दूसरा मुम्बई में हुआ। मुम्बई के अलीबाग में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 9 मजदूर मारे गए थे और 19 घायल हो गए थे। और दूसरी घटना में 24 फरवरी 2014 को कुल्लु के मणीकर्ण में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी जो बिजली विभाग के एक ठेकेदार के पास काम कर रहा था इस दर्दनाक हादसे में एक अन्य मजदूर घायल हो गया था।

संपादकीय

कार्नी का नया कनाडा

कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी की जीत भारत से संबंधों में सुधार के नजरिये से बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव से पूर्व और चुनाव के दौरान कार्नी कहते रहे हैं कि आने वाले समय में भारत से बेहतर रिश्ते बनेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की दुराग्रह और पृथक्तावादियों के दबाव के चलते भारत कनाडा संबंध अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए थे। कार्नी की जीत से उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर लौटेंगे। दरअसल, एक अपरिपक्व राजनेता की तरह जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर प्रकरण को जिस तरह तूल दिया, उसके चलते दोनों देशों के संबंध बेहद खराब स्थिति में पहुंचे। हालांकि, भारत सरकार ने निज्जर प्रकरण में हाथ होने के दावों का दृढ़ता से खंडन किया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक संबंध और लोगों के आने-जाने का उपक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ था। निस्संदेह, कार्नी का फिर सत्ता में लौटना संबंधों में सुधार का स्पष्ट संकेत है। वे अपने पूर्ववर्ती के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित आर्थिक विशेषज्ञ, व्यावहारिक राजनेता और बयानों में संतुलन रखने वाले व्यक्ति हैं। दरअसल, हाल के चुनावों में उनका 'मजबूत कनाडा, मुक्त कनाडा' का नारा खूब चला। ट्रंप के टैरिफ वार और बार-बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयानों ने कनाडा के लोगों में असुरक्षा का भाव भर दिया। कनाडाई जनमानस को पढ़ने में सक्षम कार्नी ने इस मुद्दे को हथियार बनाकर पार्टी की सत्ता में वापसी करा दी। अन्यथा कुछ समय पूर्व पार्टी के पराजय को लेकर दावे किए जा रहे थे। दरअसल, उन्होंने कनाडा को मजबूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहाल करने की बात कही ताकि घरेलू स्थिरता को मजबूत किया जा सके। निश्चित रूप से कार्नी का यह दृष्टिकोण व्यापारिक, रणनीतिक व लोगों को जोड़ने की दृष्टि से भारत के लिये महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। एक सफल केंद्रीय बैंकर और अनुभवी निवेशक के रूप में कार्नी भारतीय बाजार से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं। बहरहाल, कार्नी के कनाडा की सत्ता में वापसी और भारत विरोधी तत्वों के सिमटने से नये सिरे से व्यापार वार्ता शुरू करने, छात्र वीजा सुविधा के विस्तार और आव्रजन नीतियों में स्थिरता की उम्मीद जगी है। उनकी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बधाई देने में मजबूत साझेदारी की उम्मीद झलकती है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट से हजारों भारतीय छात्रों और आप्रवासियों का भविष्य प्रभावित हुआ। वीजा में देरी, पढ़ाई के बाद काम की चिंता और कथित रूप से कटुतापूर्ण माहौल ने एक सपनों के गंतव्य स्थल की छवि को धूमिल ही किया। बदले हुए हालात में कार्नी प्रशासन को इस वर्ग को आश्वस्त करने के लिये तेजी से काम करना होगा। वह वर्ग जो कनाडाई अर्थव्यवस्था में अरबों का योगदान देता है तथा उसके कुशल कर्मियों की संख्या को बढ़ाता है। भारत को पिछली कटुता को भुलाकर बेहतर संबंधों हेतु उदारता का परिचय देना चाहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि कार्नी प्रशासन खालिस्तानी उग्रवाद और प्रवासियों संबंधी कट्टरता जैसे संवेदनशील मुद्दों को कितने बेहतर ढंग से संभालता है। वैश्विक व्यवस्था में बदलाव और अमेरिकी राजनीति में अनिश्चितता के बावजूद भारत व कनाडा के बीच जलवायु संबंधी मुद्दों, शिक्षा और डिजिटल नवाचार में गहरी भागीदारी की संभावना पैदा हुई है। कार्नी की जीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद विश्वास में बदल सकती है।

मजदूरों के महत्व को दर्शाता मजदूर दिवस

(लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा)

(01 मई मजदूर दिवस पर विशेष)

मजदूर दिवस मजदूरों के महत्व को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य उस दिन मजदूरों की भलाई के लिए काम करने व मजदूरों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाना होता है। मगर ऐसा हो नहीं पाया है। भारत में 90 फीसदी मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित व असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा है।

भारत में एक मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में एक मई 1923 को मद्रास दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया गया था। इस की शुरुआत भारती मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाये और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाये। वर्तमान में भारत समेत लगभग 80 देशों में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।

मजदूर दिवस दुनिया के सभी कामगारों, श्रमिकों को समर्पित होता है। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की थीम है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलाइजेशन की भूमिका। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कार्यस्थल को और ज्यादा सुरक्षित और सेहतमंद बनाने में किया जाएगा। स्मार्ट हेलमेट्स, सेफ्टी सेंसर, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम ये सब भविष्य की सुरक्षा के अहम हिस्से बनेंगे। यह थीम हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित कर सकें।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है। लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक तबके में अब कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह का कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस इनके लिए सिर्फ कागजी रस्म बनकर रह गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश की तरक्की उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करती है। उद्योगपति खुद को मालिक समझने की बजाय अपने-आप को ट्रस्टी समझे। मगर ऐसा होता नहीं है। मालिक आज भी मालिक बने हुये हैं। मजदूर सिर्फ मजबूर होकर रह गया है। इसी कारण भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी अपने समय में किसानों, मजदूरों और कामगारों के हक में आवाज उठाई थी। गुरु नानक देव जी ने 'काम करना, नाम जपना, बांट छकना और दसवंध निकालना का संदेश दिया था। गरीब मजदूर और कामगार का विनम्रता का राज स्थापित करने के लिए मनमुख से गुरमुख तक की यात्रा करने का संदेश दिया था।

मजदूर एक ऐसा शब्द है जिसके बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मजदूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार हो पाया है। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती हैं मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है तो सभी पीछे हट जाती है। इसीलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है।

हमारे देश के मजदूरों को न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। गांव में खेती के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जहां ना उनके रहने की कोई सही व्यवस्था होती है ही उनको कोई ढ़ग का काम मिल पाता है। मगर आर्थिक कमजोरी के चलते शहरों में रहने वाले मजदूर वर्ग जैसे तैसे कर वहां अपना गुजर-बसर करते हैं।

बड़े शहरों में झोंपड़ पट्टी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां रहने वाले लोगों को कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करता है। इसको देखने की न तो सरकार को फुर्सत है ना हीं किसी राजनीतिक दलों के नेताओं को। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को शौचालय जाने के लिए भी घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। झोपड़ पट्टी बस्तियों में ना रोशनी की सुविधा रहती है। ना पीने को साफ पानी मिलता है और ना ही स्वच्छ वातावरण। शहर के किसी गंदे नाले के आसपास बसने वाली झोपड़ पट्टियों में रहने वाले गरीब तबके के मजदूर कैसा नारकीय जीवन गुजारते हैं। उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मगर इसको अपनी नियति मान कर पूरी मेहनत से अपने मालिकों के यहां काम करने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों के मन में जरा भी सहानुभूति के भाव नहीं रहते हैं। उनसे 12-12 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। घंटो धूप में खडे रहकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले मजदूरों को एक छप्पर तक नसीब नही हो पाता है। देश के कारखानो में काम करने वाले मजदूरो पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि ना जाने कब मालिक उनकी छटनी कर काम से हटा दे। कारखानो में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। कारखानो में श्रम विभाग के मापदण्डो के अनुसार किसी भी तरह की कोई सुविधायें नहीं दी जाती है।

(चिंतन-मनन)

विनम्रता का पाठ

चिंतन मनन

पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर-दूर तक उनकी चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित व्यक्ति रहते थे-रामसेवक। वे अत्यंत सज्जन थे और लोगों की खूब मदद किया करते थे। पंडित जी रामसेवक को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनसे दूर ही रहते थे। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक राहगीर उधर आया और मोहल्ले के एक दुकानदार से पूछने लगा-भाई यह बताओ कि पंडित विद्याभूषण जी का मकान कौन सा है। यह सुनकर पंडित जी की उत्सुकता बढ़ी। वह सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो उनके घर का पता पूछ रहा है। तभी दुकानदार ने उस राहगीर से कहा-मुझे तो किसी पंडित जी के बारे में नहीं मालूम। तब राहगीर ने कहा-क्या रामसेवक जी का घर जानते हो?

दुकानदार ने हंसकर कहा-अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने हाथ दिखाकर कहा- वो रहा रामसेवक जी का घर। फिर दुकानदार ने राहगीर से सवाल किया-लेकिन आपको काम किससे है? पंडित जी से या रामसेवक जी से? राहगीर कहने लगा-भाई काम तो मुझे रामसेवक जी से है। पर उन्होंने ही बताया था कि उनका मकान पंडित विद्याभूषण जी के पास है। यह सुनकर पंडित जी ग्लानि से भर उठे। सोचने लगे कि उन्होंने हमेशा ही रामसेवक को अपने से हीन समझा और उसकी उपेक्षा की पर रामसेवक कितना विनम्र है।

वह खुद बहुत प्रसिद्ध होते हुए भी उन्हें ज्यादा महत्व देता है। उसी रात पंडित जी रामसेवक के घर गए और उससे क्षमायाचना की। फिर दोनों गहरे मित्र बन गए।

विचार मंथन

सीरिया से बदतर हो जाएंगे पाकिस्तान के हालात

(लेखक- डॉ हिदायत अहमद खान)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो देश के अंदर मौजूद हों या फिर सीमापार। इससे किसी भी शांतिप्रिय व्यक्ति या देश को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि ऐसे आतंकियों को सजा दिलाने में सभी को साथ आना चाहिए, ताकि दुनियां में यह संदेश जा सके कि निर्दोष और निहत्थों पर जुल्म और ज्यादती करने और बेरहमी से जान लेनें वालों की इस दुनियां में न तो कोई जगह है और न ही किसी को उनकी जरुरत है। पर अफसोस कि आतंकवाद को पालने और दरिंदों की फौज तैयार कर पड़ोसियों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करने की जो रणनीति पर चल रहा हो, वह शांति और भाईचारे की बात को कैसे समझ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो इमारत नफरत की नींव पर खड़ी की गई हो उसमें सुख-समृद्धि और भाईचारा कैसे निवास कर सकता है। बगावत और हमेशा कत्लेआम की भाषा बोलने वाले प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ ही नहीं सकते। इसके चलते बहुतायत में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी पनपती है और फिर शुरु होता है अपनों और परायों का फर्क किए बगैर छल-कपट और फरेब के साथ ही खून-खराबे का वो दौर जो इस समय पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो विभाजन के बाद से पाकिस्तान कभी सुकून से बैठा ही नहीं। राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद को पालने का परिणाम बांग्लादेश के तौर पर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाना हमेशा। उसके दिल में इसकी टीस सदा ही उभरती होगी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके सही रास्ते पर आने की जगह पाकिस्तान अपने ढर्रे पर कायम रहा, नतीजा पीओके और बलूचिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बगावत के सुर और बड़ी तादाद में हिंसा का होना है। अब यदि वह कुछ और करने की सोचता भी है तो बिना कुछ किए एक और प्रांत अलग देश बनाने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान की संसद में इसको लेकर बात भी हो चुकी है, जिसे एक सांसद ने यह कहते हुए बतला दिया था कि इस अशांत प्रांत के 12 जिलों में विद्रोही गुटों की आजाद सरकारें चल रही हैं। मतलब साफ है कि जहां आवामी सरकार के पैररल किसी संगठन की अपनी सरकार चल रही हो, वहां के हालात कैसे हो सकते हैं।

इस समय पाकिस्तान के कुछ मंत्री समेत नेता भी भारत को गीदड़भभकी देने का काम कर रहे हैं। परमाणु संपन्न होने का वो दम भर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बात यह है कि यदि वाकई युद्ध होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद विद्रोही गुट क्योंकर खामोश बैठेगा। वह भी मौका देख अपने मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेगा। स्थिति सीरिया से भी बदतर हो जाएगी और एक और जख्म देश टूटने का पाकिस्तान को सहना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि देश के हालात से पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज सरकार नाबाकिफ है, लेकिन इससे निकला कैसे जाए यह उसे सूझ ही नहीं रहा है। गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो खुद इस समय जेल में हैं कह रहे हैं कि पहलगाम घटना में लोगों की जान जाना बेहद परेशान करने वाला और दुखद है। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वो पुलवामा घटना को याद करते हुए आगे कहते हैं कि जब पुलवामा की घटना हुई थी, तब हमने भारत को हरसंभव सहयोग करने की पेशकश की थी, लेकिन भारत तब कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। इसके साथ ही इमरान ने यह भी कह दिया कि उन्होंने तो पहलगाम जैसी घटना की 2019 में ही भविष्यवाणी कर दी थी। वैसे इमरान की बात ज्यादा इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि उन्हें खुद अपने भविष्य का पता नहीं है। कब जेल से छूटेंगे और कब अपने विरोधियों के दिए हुए जख्मों का बदला ले पाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में जुल्फीकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ और भी कई बड़े नेताओं का हश्र तो दुनियां देख ही चुकी है।

इन तमाम घटनाओं के लिए किसी विदेशी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। बहरहाल इस समय पाकिस्तान को चाहिए था कि वो आगे आता है और आतंकवाद को खत्म करने भारत से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए युद्ध की भाषा बोली जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने जलपोत निर्माण नीति को मंजूरी दी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जलपोत निर्माण, उनकी मरम्मत, पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक नीति मंजूर की है। जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति, 2025 के तहत इस क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं को पूंजीगत सब्सिडी, कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता और रियायती दरों पर या दीर्घकालिक पट्टे पर जमीन दी जाएगी।राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में अपनी बैठक में नीति को मंजूरी दी।बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जलपोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने का संकल्प लिया है।

फिलिप्स को भारतीय कारोबार बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली। नीदरलैंड की एक अमरीकी कंपनी फिलिप्स ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की उम्मीद जताई है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख ने बताया कि उन्हें भारत में अपने कारोबार को दहाई अंकों में बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के अगले पांच वर्षों में भारत में बड़ी उपलब्धियों की आशा है और उसके लिए दहाई अंकों की वार्षिक वृद्धि से मदद मिलेगी। फिलिप्स के अधिकारी ने यह भी कहा कि कंपनी न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि अपने वैश्विक बाजारों के लिए भी घरेलू सोर्सिंग को प्रोत्साहित कर रही है। फिलिप्स इंडिया के वित्त वर्ष 2023-24 में एकल आधार पर परिचालन राजस्व 6,000.4 करोड़ रुपये था, जो सालाना आधार पर 4.64 प्रतिशत अधिक था।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए नए अवसर- एचसीएल समूह

नई दिल्ली। एचसीएल समूह ने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के बीच प्रौद्योगिकी उद्योग को सतर्क रूप से आशावादी बताया। एचसीएल समूह के एक वे रिष्ठ अे धिकारी के मुताबिक अमेरिकी शुल्क और मुद्रास्फीति के दबाव से लागत-अनुकूलन की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, जो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने कहा` कि हम आशावादी हैं, क्योंकि हम इन उद्योगों के ग्राहकों के लिए काम करते हैं, जो शुल्क से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े बाजार अमेरिका है और यह यहाँ का संदेश को बचाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग और सुनें को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा कि लागत अनुकूलन ही एकमात्र विकल्प है जिससे शुल्क दबावों और मुद्रास्फीति के बीच वृद्धि का मुकाबला किया जा सकता है।

बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मुनाफा बढ़ा

मुंबई। शेयर बाजार में बजाज ग्रुप के दोनों बड़े नाम, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने मुनाफे भरे नतीजे पेश कर` दिए हैं। बजाज फाइनेंस ने अपने शेयरधारकों को 56 रुपये डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान किया है। बजाज फाइनेंस का मुनाफा मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में 16 प्रतिशत बढ़कर 3,940 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 3,402 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 44 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड और 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी घोषित किया है। विपक्ष में बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मुनाफा मार्च 2025 को समाप्त चौथी तिमाही में 14 प्रतिशत बढ़कर 2,417 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने निदेशक मंडल की सिफारिश पर एक रुपये प्रति शेयर के 100 प्रतिशत लाभांश की सिफारिश की है। इससे कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश 56 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा और शेयरधारकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया गया है।

रेनॉल्ट कंपनी चेन्नई में नया डिजाइन स्टूडियो स्थापित करेगी

नई दिल्ली।

हाल ही में रेनॉल्ट कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई रणनीति का खुलासा किया, जिसमें चेन्नई में एक नया डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना शामिल है। यह डिजाइन केंद्र यूरोप के बाहर रेनॉल्ट का सबसे बड़ा स्टूडियो होगा। इसके साथ ही, रेनॉल्ट की योजना अगले दो वर्षों में भारत में पांच नए मॉडल्स लॉन्च करने की है, जिसमें तीसरी पीढ़ी की डस्टर और इसका सात सीटों वाला वर्जन बिगस्टेर शामिल है। रेनॉल्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डस्टर और इसके तीन-रो वर्जन के लिए डीजल इंजन का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि कंपनी आगामी एसयूवी मॉडल्स के लिए हाइब्रिड पावरट्रेन लाने की योजना बना रही है। में डिजाइनिंग स्टूडियो के उद्घाटन के दौरान, रेनॉल्ट इंडिया के सीईओ वेंकटराम ममिल्लापल्ले ने हाइब्रिड और सीएनजी विकल्पों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि रेनॉल्ट भारतीय बाजार के लिए व्यावहारिक हाइब्रिड विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड को खारिज किया गया है, क्योंकि उनका बाजार में प्रभाव कम होता है। इसके अलावा, रेनॉल्ट रेंज एक्सटेंडर तकनीक का भी मूल्यांकन कर रहा है, जो एक छोटा आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का संयोजन होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, रेनॉल्ट तीसरी पीढ़ी की डस्टर के हाइब्रिड वेरिएंट्स में 1.6-लीटर चार-सिलेंडर इंजन का उपयोग करेगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.2 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ जुड़ेगा, जिससे कुल 138 बीएचपी का पावर आउटपुट मिलेगा।

सस्ते स्टेनलेस स्टील आयात से सुरक्षा देने कदम उठाए सरकार: उद्योग निकाय

नई दिल्ली। भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ ने स्थानीय विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार से सुरक्षात्मक शुल्क जैसे कदम उठाने का आग्रह किया है। इस चुनौती से निपटने के लिए उद्योग और सरकार दोनों को मिलकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। भारत में तैयार स्टील के बढ़ते आयात ने स्थानीय उद्योगों को असहाय बना दिया है। उच्च लागत और अनियमितता के कारण स्थानीय उत्पादकों का व्यावसायिक संसाधनों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। चीन से सस्ता आयात कर मार्ग से भारत में पहुंच रहा स्टेनलेस स्टील ने स्थानीय उद्योगों को कठिनाई में डाल दिया है। एक बाजार अनुसंधान फर्म के मुताबिक स्टेनलेस स्टील आयात की मात्रा में वृद्धि की दिशा में एक चिंताजनक रुख देखने को मिल रहा है। इस पर कार्यवाही के लिए होने वाले संगठन पहल से संबंधित कागजात पेश करने के लिए तैयार हैं। उद्योग के हितधारक जून में होने वाले वैश्विक स्टेनलेस स्टील शिखर सम्मेलन 2025 में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। यहां कई उत्थानशील विचारक और निर्माताजनों को एक समायोजन में आकर्षित करना है।

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर में तेजी, 3 दिन में 35 फीसदी चढ़ा

नई दिल्ली।

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर में तेजी बनी हुई है। डिफेंस कंपनी के शेयर बुधवार को 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 1469 रुपए पर पहुंचे। पारस डिफेंस के शेयरों में 3 दिन में 35 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर मंगलवार को 17 फीसदी और सोमवार को 9.5 फीसदी का उछल आया था। डिफेंस कंपनी बुधवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया। कंपनी अपने शेयरों के बंटवारे की भी घोषणा भी की। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का बोर्ड बुधवार की बैठक में शेयरों के बंटवारे को मंजूरी दी। कंपनी का बोर्ड अगर स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी देता है तो पारस डिफेंस पहली बार अपने शेयरों का बंटवारा करेगी। पारस डिफेंस के शेयर पिछले एक साल में 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए। डिफेंस कंपनी के शेयर 30 अप्रैल यानी बुधवार को 726 रुपए पर थे। पारस डिफेंस के शेयर बुधवार को 1469 रुपए के स्तर पर जा पहुंचे। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1592.75 रुपए है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 681.95 रुपए है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का दाम 175 रुपए था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 सितंबर 2021 को खुला था और यह 23 सितंबर 2021 तक ओपन हुआ था। पारस डिफेंस के शेयर 1 अक्टूबर 2021 को बीएसई में 475 रुपए पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ 498.75 रुपए पर बंद हुए। पारस डिफेंस का आईपीओ टोटल 304.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अगर पिछले दो साल की बात करें तो पारस डिफेंस के शेयरों में 165 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट बिकवाल हावी रहने के साथ ही दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के बीच ही वित्तीय शेयरों में गिरावट से आई है। आज कारोबार के दौरान दिग्गज कंपनियों बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयरों के टूटने से भी बाजार नीचे आया हालांकि मारुति सहित वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार की गिरावट पर कुछ अंकुश लगा। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 46.14 अंक करीब 0.06 फीसदी नीचे आकर 80,242.24 अंक पर बंद हुआ। वहीं पचास शेयरों पर अधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अंत में 1.75 अंक तकरीबन -0.01 फीसदी की हल्की गिरावट के साथ ही 24,334.20 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान चौथी तिमाही के परिणाम कमजोर रहने से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर 5.18 फीसदी और 5.44 फीसदी नीचे आये। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बंद रहेगा। वहीं भारत-पाक तनाव को लेकर भी निवेशक सतर्क रुख अपनाये हुए हैं। वहीं गत दिवस बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था। इससे पहले आज सुबह बाजार बुधवार को` गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स मामूली वृद्धि के साथ 80,370.80 अंक पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजका निफ्टी-50 24,342.05 अंक पर खुला। खुलते ही इंडेक्स गिरावट में चला गया। यह 48.65 अंक की गिरावट लेकर 24,287.30 पर कारोबार कर रहा था। वहीं दुनिया भर के बाजार की बात करें तो अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। डाऊ जोंस 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 40,527.62 पर बंद हुआ जबकि एसएंडपी 500 0.58 फीसदी बढ़कर 5,560.83 और नैस्डेक कंपोजिट 0.55 फीसदी की बढ़त के साथ 17,461.32 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार सुबह एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला, क्योंकि निवेशक कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत फैसलों का इंतजार कर रहे थे।

जापान का निक्की 225 0.22 फीसदी चढ़ा, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.34 फीसदी ऊपर रहा, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स और चीन का सीएसआई 300 दोनों में 0.14 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 70.01 अंक की बढ़त लेकर 80,288.38 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7.45 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,335.95 पर बंद हुआ।

ब्रिजस्टोन इंडिया ने हैदराबाद में ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर्स का विस्तार किया

हैदराबाद में ब्रिजस्टोन के कुल स्टोरों की संख्या 46 हुई

नई दिल्ली।

भारत में टायर उद्योग की अग्रणी कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया ने हाल ही में हैदराबाद में अपने प्रमुख ब्रिजस्टोन सेलेक्ट स्टोर्स का विस्तार किया है। चार नए प्रीमियम आउटलेट्स की उद्घाटन समारोह में ब्रिजस्टोन इंडिया के एक प्रमुख अे धिकारी ने उनकी इस पहल को समर्थन दिया। इस नए विस्तार के साथ हैदराबाद में ब्रिजस्टोन के कुल स्टोरों की संख्या 46 हो गई है। देशभर में कंपनी के डीलर नेटवर्क की संख्या भी 3,200 तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 820 सेलेक्ट प्रीमियम स्टोर्स शामिल हैं। ये स्टोर दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु, कोल्हापुर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में स्थित हैं। ब्रिजस्टोन इंडिया के अे धिकारी ने कहा` कि हैदराबाद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। सेलेक्ट स्टोर्स का यह विस्तार ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी जागरूकता और अनुभव को भी आगे बढ़ाएगा। हमारी प्रतिबद्धता हमेशा से उच्च गुणवत्ता के साथ समाज की सेवा करने की रही है।

भारत का टायर बाजार हर साल लगभग 4.4 करोड़ यूनिट्स के स्तर तक पहुँचता है, जिसमें करीब 2 करोड़ यूनिट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (और 2.4 करोड़ यूनिट्स आफ्टरमार्केट सेगमेंट में होती हैं। ब्रिजस्टोन का आफ्टरमार्केट में लगभग 20 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है और ओईएम सेगमेंट में यह कंपनी मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और होंडा जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ कार्य करती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों पर विशेष योजना की शुरू

30,000 करोड़ रुपये के निवेश का रखा लक्ष्य

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बुधवार को यहां 'तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना' की शुरुआत की। राज्य सरकार की इस विशेष पहल से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया` कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने और 60,000 नौकरियां सृजित करना है। तमिलनाडु ने इससे पहले मूल्यवर्धित विनिर्माण को और बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर उप-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर व उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2024 शुरू की थी। इस नीति ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन में तमिलनाडु को अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के इन प्रयासों को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने अब इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पर केंद्रित इस विशेष योजना की शुरुआत की है। इसमें कहा गया`` कि तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना' केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चीनी उत्पादों के उच्च शुल्क का असर

अप्रैल में उत्पादों के निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई

हांगकांग।

चीन से विभिन्न उत्पादों के आयात पर लगाए गए अमेरिकी उच्च शुल्कों का असर अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर` दिखाई दे रहा है। चीन के लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग फेडरेशन ने जारी किया गया आधिकारिक सर्वेक्षण में बताया है कि अप्रैल में उत्पादों के निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई है। अमेरिकी प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 145 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने का आदेश दिया था, जिसका प्रभाव अब उसके निर्यात पर`` दिखाई दे रहा है। वहीं चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया है। इस परिस्थिति में आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने 16 महीनों का सबसे निचला स्तर दर्शाते हुए मार्च में 49.0 पर पहुंच गया।

वित्तीय सूचना समूह कैक्सिन ने भी एक निजी सर्वेक्षण के माध्यम से बताया कि पीएमआई कम होकर 50.4 पर पहुंच गया है। इस विचार को लेकर कि कैपिटल इकोनॉमिसस्ट ने कहा कि यह गिरावट व्यापक शुल्क के प्रभाव को दिखाती है, जो चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में आपूर्ति और मांग में वृद्धि धीमी रही, निर्यात में कमी आई और रोजगार में थोड़ी कमी आई। विनिर्माताओं ने भंडार कम करने की मांग की, रसद में देरी हुई और कीमतें दबाव में रहीं। निजी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान में भी कमी आई है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट के अनुमान के मुताबिक, 2025 में अर्थव्यवस्था केवल 3.5 प्रतिशत बढ़ेगी। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएफएफ) ने अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भविष्य के लिए भी कमी के संकेत दिए हैं।

जनवरी में लगाए गए 3.3 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत, आईएफएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के लिए 2.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया है।

अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी के भाव में गिरावट

सोने के भाव 95,150 रुपए, चांदी 96,000 रुपए के करीब

नई दिल्ली।

अक्षय तृतीया के अवसर पर बुधवार को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। दोनों के वायदा भाव बुधवार को गिरावट के साथ खुले। घरेलू बाजार में सोने के भाव 95,150 रुपये, जबकि चांदी के भाव 96,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क जून कॉन्ट्रैक्ट 239 रुपये की गिरावट के साथ 95,353 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 95,592 रुपये था। इस समय यह 428 रुपये की गिरावट के साथ 95,164 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मई कॉन्ट्रैक्ट 749 रुपये की नरमी के साथ 96,113 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 96,862 रुपये था। इस समय यह 832 रुपये की गिरावट के साथ 96,030 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव के भाव में नरमी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 3,324.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 3,333.60 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 15.30 डॉलर की गिरावट के साथ 3,318.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव पिछले सप्ताह 3,509.90 डॉलर के भाव पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 32.89 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 33.27 डॉलर था। इस समय यह 0.39 डॉलर की गिरावट के साथ 32.88 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सेबी ने अडानी ग्रुप और उसके विदेशी निवेशकों को दिया झटका

-सैटलमेंट के अनुरोध को रखा स्थगित, नियमों की कर रही समीक्षा

नई दिल्ली।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी ग्रुप और उसके विदेशी निवेशकों को झटका दिया है। सेबी ने आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा होने तक नियामकीय शुल्कों का सैटलमेंट करने के अनुरोध को स्थगित रखा है। बीते दिनों सेबी ने बताया था कि सैटलमेंट याचिकाओं के नियमों की समीक्षा की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटलमेंट प्रक्रिया में एकरूपता की कमी और लगाए गए दंड की प्रकृति पर अस्पष्ट नियमों की वजह से समीक्षा की जा रही है। एक सूत्र ने कहा कि समीक्षा में तीन महीने का समय लग सकता है जिसके बाद अडानी की याचिकाओं पर नई प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक अडानी ग्रुप की 30 संस्थाओं ने इनमें से कुछ विनियामक शुल्कों का सैटलमेंट करने के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट में सूत्र ने बताया कि अडानी ग्रुप की याचिकाएं निपटान के लिए लंबित तीन सौ से ज्यादा आवेदनों में से हैं, लेकिन सबसे प्रमुख की समीक्षा की जा रही है। बता दें सेबी की सैटलमेंट प्रक्रिया के तहत निवेशक और बाजार सहभागी बिना किसी अपराध के स्वीकारोक्ति या इनकार के मौद्रिक जुर्माना भरते हैं या विनियामक निर्देशों से सहमत होते हैं। इससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी ने बताया था कि समूह के संस्थापक चेयरमैन गौतम अडानी और दो अन्य कंपनी अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाए जाने के मामले में नियामकीय अनुपालन की एक स्वतंत्र समीक्षा में कोई भी अनियमितता या गैर-अनुपालन नहीं पाया है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी उनके भतीजे और कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और प्रबंध निदेशक विनीत एस जैन पर सौर ऊर्जा अनुबंध पाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की कथित योजना में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा इन पर अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने की कोशिश करते समय अपनी योजना को छुपाने का आरोप भी लगा था। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी पर आरोप है कि सौर ऊर्जा बिक्री अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी गई। इस अनुबंध से कंपनी को 20 साल की अवधि में दो अरब डॉलर का लाभ होने का अनुमान था। अडानी ग्रुप ने पहले सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया था और कहा था कि वह अपना बचाव करने के लिए कानूनी विकल्प अपनाएगा।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में तेजी

भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेगा

वाशिंगटन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार शुल्क को लेकर बातचीत की प्रगति का संकेत दिया। उनकी घोषणा ने व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी है। ट्रंप ने यह बयान मिशिगन में होने वाली एक रैली से पहले दिया। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि वह अफ्रीका दौरे की योजना बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। एक समाचार एजेंसी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में एक ऐसा लुभावना प्रस्ताव शामिल करने जा रही है, जिससे यह समझौता भविष्य में भी सुरक्षित बना रहे। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी अन्य व्यापारिक साझेदार को इससे बेहतर शर्तें न मिलें।

यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार फॉरवर्ड मोस्ट-फेवर्ड-नेशन क्लॉज शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसे पहले के व्यापार समझौतों में केंद्र सरकार ने बहुत कम ही मंजूरी दी है। इस क्लॉज के तहत अमेरिका को यह सुविधा मिलेगी कि अगर भारत भविष्य में किसी और देश को बेहतर टैरिफ शर्तें देता है, तो वे शर्तें अपने आप अमेरिका पर भी लागू हो जाएंगी।

बीते मंगलवार को अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत उन पहले देशों में शामिल हो सकता है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेगा। इसी सेंटीमेंट को अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने भी दोहराया।

पुलिस की विशेष टीमें रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की कर रहीं तलाश

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी पुलिस का कहना है कि उन्हें पर्यटन स्थलों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मूवमेंट का इनपुट मिला है। यहां तक कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मंदिरों और अन्य प्रमुख स्थलों पर ये लोग फेरीवाला और मांगने वालों के वेश में रह रहे हैं। इनकी तलाश और शिनाख्ती का काम अब विशेष पुलिस की टीमें करेंगी। पुलिस के मुताबिक कई सालों से यहां रहने के कारण इन्हें भाषाई या पहनावे से पहचानना थोड़ा जटिल हो गया है। बावजूद इसके किराए का मकानों का सत्यापन और भाषाई जानकारी हासिल कर इन रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की मौजूदगी को उजागर किया जा सकेगा। पुलिस की विशेष टीम अब सड़कों व रेल पटरियों के किनारे, गांव के बाहरी क्षेत्रों, पार्कों और खुले मैदानों में रहने वाले लोगों का भी सत्यापन कर सकेगी। ऐसा करते हुए इन लोगों को चिह्नित कर हटाया जाएगा। यहां बताते चलें कि एटीएस और एनआईए द्वारा गठित टीमें पहले से ही रोहिंग्या की तलाश में जुटी हुई हैं। तलाशी के दौरान पिछले दिनों सारनाथ से दो लोगों को पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर वाराणसी के काशी, गोमती और वरुणा समेत तीनों जोन की विशेष पुलिस टीमें भी इस पर प्रभावी विधिक कार्रवाई को अंजाम देंगी।

मई की शुरुआत होगी बारिश व आंधी से, दिल्ली-एनसीआर में चलेंगी तेज हवाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मई की शुरुआत बारिश व आंधी से होगी। तापमान घटेगा और गर्मी से एक सप्ताह तक दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मई महीने के शुरुआती हफ्ते में बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि 1-3 मई तक तेज हवाओं के आंधी में तब्दील होने की वजह से 'येलो अलर्ट' जारी किया है। आइएमडी के मुताबिक 1-3 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं हवाओं की रफ्तार 30-40 किमी प्रतिघंटा व कुछ इलाकों में 50 किमी प्रतिघंटा से चलेंगी जोकि आंधी का रूप ले सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। वहीं 4-5 मई को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होगी लेकिन हवाओं की गति धीमी पड़ रहेगी। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 37.5 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 अधिक 24.5 दर्ज किया गया। मंगलवार सुबह पूर्वी सतही हवाओं की रफ्तार 15-20 किलोमीटर से बढ़कर शाम के समय 37 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान में गिरावट पालम निगरानी केंद्र में देखने को मिली। दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस बनी हुई है। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में मॉनसूनी पूर्व बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है।

मानहानि के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी, अब 17 मई को होगी अगली सुनवाई

लखनऊ (एजेंसी)। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रुप से आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने आरोपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में बताया कि 29 अप्रैल को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है लिहाजा वे हाजिर नहीं हो सके। विदित हो कि सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा के दौरान नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया और कहा ' ' लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। नौ तारीख को सीमा पर चीनी भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी करके बताया गया कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले में कहा भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान से परिवादी को आघात लगा है। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवार और वादी की मानहानि हुई है।

तेजस्वी का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा, जो पूरा नहीं होगा : गिरिराज सिंह

पटना (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष की बयानबाजी और उठाए गए सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे। दरअसल माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा सिंधु जल समझौता रोकने पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने माले को चीन का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि पानी रोकने की बात पर जनता को दोष देना गलत है, लेकिन यह वहीं लोग हैं जिन्होंने 1962 में हमारी लड़ाई के समय चीन का साथ दिया था। वहीं तेजस्वी यादव के खुद को सीएम फेस बताने पर केंद्रीय मंत्री सिंह ने तंज करते हुए कहा तेजस्वी का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर किसानों और नौजवानों तक हर वर्ग से संवाद बनाए रखा है। साथ ही पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस और राजद नेताओं के बयानों को शर्मनाक बताया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना पहुंचते ही कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री पर बयान बाजी करने पर कहा कि आज सारा देश एक है निश्चित तौर पर सभी को एकजुट होना चाहिए।

मणिपुर के 21 विधायकों ने की गृहमंत्री अमित शाह से सरकार के गठन की मांग

-पत्र में लिखा- राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी राज्य में शांति नहीं

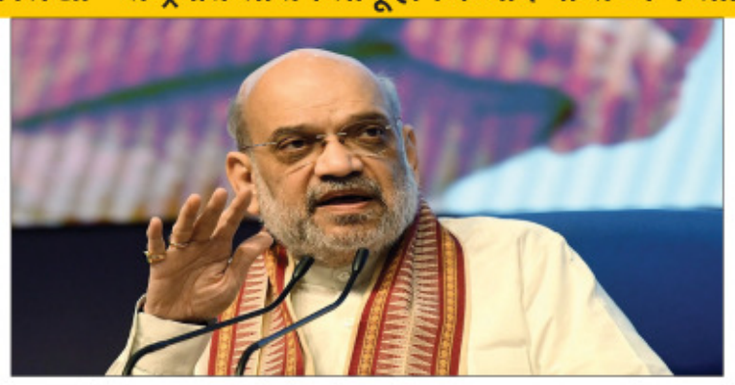

इंफाल(एजेंसी)। मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में सरकार बनाने की मांग की है। ये विधायक मणिपुर में शांति बहाली और सामान्य स्थिति की ओर कदम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। पत्र में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शांति नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोग हिंसा फिर होने की आशंका जता रहे हैं।

गौरतलब है कि 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद से मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल निलंबित कर दिया है और राज्य में शांति की बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर में मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा की स्थिति ने राज्य को काफी प्रभावित किया है।

बता दें मई 2023 से जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। पत्र में 21 विधायकों ने सरकार से अपील की है कि राष्ट्रपति शासन के बाद शांति और सामान्य स्थिति के लिए अब तक कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में बीजेपी के 13, एनपीपी के 3, नगा पीपुल्स फ्रंट के 3 विधायक और विधानसभा के 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं।

मणिपुर में अभी तक शांति और सामान्य स्थिति के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में चिंता जताई जा रही है कि राज्य में फिर से हिंसा की स्थिति बन सकती है। कई नागरिक संगठन भी राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सामने आकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि शांति के लिए सरकार का गठन अत्यंत जरूरी है। उनका मानना है कि राष्ट्रपति शासन के तहत स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है और अब स्थायी सरकार ही राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली कर सकती है।

यह पत्र गृह मंत्रालय को 29 अप्रैल यानी मंगलवार को मिला था और इसे आज सार्वजनिक किया गया। मणिपुर के इस संकटपूर्ण समय में इस पत्र को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की स्थिरता के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील करता है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाक को दी धमकी

जम्मू (एजेंसी)। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी है। इस गैंग की धमकी से जुड़ा सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें गैंग ने लिखा है कि पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब देने के लिए हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे, जो एक लाख के बराबर होगा। पोस्ट में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का फोटो भी लगा है और उस पर क्रॉस का चिह्न लगाया गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका लॉरेंस बिश्नोई गिरोह अवसर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने गुनाहों की जिम्मेदारी लेता रहा है। हालांकि उसके इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है और क्या इसे गैंग ने ही पोस्ट किया है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। अक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पाकिस्तानी गैंगस्टरों और डॉन से रिश्ते रखने के आरोप लगते रहे हैं। कई अपराधों में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान से रिश्तों की बात कहते हुए सबूत भी दे चुकी है लेकिन जेल से हुए लॉरेंस बिश्नोई के कथित इंटरव्यू में वह इस बात को नकार चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को देशभक्त कहते हुए बार-बार दावा किया था कि देश के दुश्मनों से उसके कोई रिश्ते नहीं हैं। इसके विपरीत पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को ईद की बधाई दे रहा था। यही नहीं, गैंग के शूटरों को हथियारों की सप्लाई भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होती है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान से आए एके-47 राइफल के अलावा पॉइंट 30 बोर और नौ एमएम पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था।

पंजाब ने घटाया हरियाणा को मिलने वाला पानी, गहराया जल संकट

-सीएम सैनी बोले- आश्वासन देकर पलट गए सीएम मान

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम से हरियाणा को दी जाने वाली पानी की आपूर्ति में कटौती कर दी। पहले जहां रोज 9,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा था, अब यह घटाकर केवल 4,000 क्यूसेक कर दिया है। इससे हरियाणा के करीब छह जिलों में जल संकट खड़ा हो गया है, जो आने वाले दिनों में और भी विकराल हो सकता है।

इस विवाद के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने को कहा कि राज्य के पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि भगवंत मान ने उन्हें इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की निगरानी में हर साल पंजाब सरकार हरियाणा और राजस्थान को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। यह जल आवंटन 21 मई से अगले साल की 21 मई तक मान्य होता है। इस नहर के जरिए से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। यह पानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खासकर उन इलाकों में जहां भूजल की कमी है।

पंजाब का कहना है कि हरियाणा पहले ही मार्च में अपनी तय सीमा का पानी खर्च कर चुका है, क्योंकि उसका जल प्रबंधन सही नहीं था। इससे अब पंजाब ने हरियाणा को दिए जाने वाले पानी में 5,000 क्यूसेक की कटौती कर दी है। इसका असर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और महेन्द्रगढ़ जैसे जिलों में दिखने लगा है। हालात यही रहे तो अन्य जिलों में भी पानी का संकट गहरा सकता है। मंगलवार को दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके बाद भगवंत मान ने वीडियो संदेश जारी करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा ने पानी का किफायती और समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से वह मार्च में ही अपना कोटा खत्म कर बैठा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पंजाब मानवता के आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी दे रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक वह भी नहीं दिया जाना चाहिए।

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत: गोयल

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज मंगलवार को लंदन में भारत-यूके व्यापार गोलमेज बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत है। गोयल ने निवेश के नए अवसरों और इनोवेशन-आधारित विकास की संभावनाओं पर जोर दिया। इस बैठक में दोनों देशों के बड़े व्यापारिक नेताओं और सीईओ ने भाग लिया। पीयूष गोयल फिलहाल पांच दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं। इस दौरान वे लंदन (यूके), ओस्लो (नॉर्वे) और ब्रुसेल्स (यूरोपीय संघ) की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है।

गोयल ने लंदन यात्रा की शुरुआत में यूके के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जे. रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। उन्होंने इस बैठक को ÷उपयोगी÷ बताया और कहा कि यह भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह समझौता 26 अध्यायों में बंटा है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। भारत और यूके जल्द से जल्द इसे पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण वैश्विक व्यापार में चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

गोयल ने लंदन में डी बीयर्स ग्रुप के सीईओ एल कुक और उनकी टीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रत्न और आभूषण उद्योग में भारत की भूमिका, टिकाऊ प्रथाएं और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने रेवोल्ट के चेयरपर्सन मार्टिन गिल्बर्ट से भी मुलाकात की और भारत के फिनटेक सेक्टर में वैश्विक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से भारत में नवाचार और विकास को गति मिलेगी।

युद्ध की आहट के बीच, सामान्य नहीं है भागवत का पीएम मोदी से मिलना

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीते रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक दोनों की बातचीत होने के बाद सवाल ये है कि क्या ये शिष्टाचार भेंट थी? बात क्या है ये तो कोई नहीं जानता पर, इतना जरुर माना जा रहा है कि पीएम मोदी और संघ प्रमुख भागवत की इस मुलाकात को सामान्य नहीं माना जा सकता है। वजह ये है कि संघ प्रमुख का राजनीतिक हस्तियों से मिलना बेहद असामान्य माना जाता है। संघ सूत्रों ने पुष्टि की है कि 2014 में पीएम मोदी के पदभार संभालने के बाद से यह पहली ऐसी मुलाकात थी। मुलाकात से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मोहन भागवत ने इस घटना पर संघ परिवार की गहरी पीड़ा और हिंदू समुदाय में बढ़ते गुस्से और असुरक्षा की भावना से अवगत कराया। उन्होंने आतंकी हमले का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के प्रयासों के प्रति संघ का समर्थन भी दिया। आरएसएस के एक सीनियर पदाधिकारी ने बताया, 'यह महज शिष्टाचार भेंट नहीं थी। जमीनी स्तर पर माहौल तनावपूर्ण है। हिंदू आहत और नाराज हैं। संघ का मानना ??है कि सरकार के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनभावनाओं को समझा जाए और जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जाए। यह इमरजेंसी का समय है और इसलिए भागवत जी ने खुद पीएम से मुलाकात की। मोहन भागवत की यह मुलाकात प्रतीकात्मक और रणनीतिक रूप से अहम तो है ही, लेकिन इससे जो संदेश जाता है, वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने विशाल जनाधार और वैचारिक प्रभाव के साथ संघ परिवार के पास जनमत बनाने और सरकार की आवश्यकतानुसार समर्थन जुटाने या उसे नियंत्रित करने की क्षमता है। सरकार इस ताकत से वाकिफ है। माना जा रहा है कि वह जनभावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने अगले कदम सावधानी से उठा रही है। आरएसएस के एक अन्य सीनियर पदाधिकारी ने कहा, अगर सरकार को निर्णायक जवाबी कार्रवाई के पक्ष में स्पष्ट और मजबूत जनमत का आभास होता है, तो वह उस दिशा में तेजी से और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ सकती है। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन महत्वपूर्ण है। बता दें कि यह मुलाकात पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद हुई है, जहां निहत्थे नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बनाकर मार डाला गया था।

20 मई से फिर बिहार में हुंकार भरेंगे प्रशांत किशोर, बोले- लोग बदलाव चाहते हैं, जातिगत जनगणना पर भी कही बड़ी बात

पटना (एजेंसी)। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा कि बिहार के लोग शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार न होने के कारण बदलाव चाहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए किशोर ने कहा कि बिहार में एक बात तो तय है-लोग बदलाव चाहते हैं। चाहे वे आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के समर्थक हों या किसी भी जाति या धर्म के हों, वे बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30-35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देखा है। शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है। वे दूसरे राज्यों में विकास देखते हैं और ठगा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें ऐसी किसी जनगणना या सर्वेक्षण से कोई दिक्कत नहीं है जो समाज की बेहतर समझ देता हो, लेकिन हमने बिहार में देखा है कि केवल जातिगत सर्वेक्षणों से देश की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि यह तभी संभव होगा जब सरकार सर्वेक्षणों से निकले निष्कर्षों के आधार पर काम करेगी। किशोर ने सुझाव दिया कि बदलाव अपरिहार्य है, हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने कहा, 'इस पर बहस हो सकती है कि बदलाव का अगुआ कौन होगा। यह जन सुराज हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वे (लोग) बदलाव चाहते हैं।' किशोर ने आगे कहा कि जन सुराज 20 मई को 'बिहार बदलाव यात्रा' शुरू करेगा। यात्रा से पहले, पार्टी 11 मई को राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को निशाना बनाया जाएगा। किशोर ने कहा, ÷हम बिहार में एक करोड़ लोगों से तीन मुद्दों- जाति जनगणना, दलित महादलित परिवारों को भूमि वितरण और भूमि सर्वेक्षण पर नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे।÷ जन सुराज अपना पहला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जो इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। पार्टी ने पहले उपचुनाव लड़े थे, लेकिन चुनावी प्रभाव छोड़ने में विफल रही। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुआ था। किशोर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने कहा, 'विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे मामलों में हर नागरिक, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न जुड़ा हो, सरकार के साथ खड़ा होता है।' जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को बैसरन मैदान में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले में 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।

पहलगाम हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने किया पीएम मोदी का समर्थन

-कहा- हमारे पास भी परमाणु बम है, अगर दुश्मनी चाहते हो तो हम तैयार हैं

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी के लिए समर्थन जताया है। इसके साथ फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के गायब होने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान को आगे की उकसावेबाजी के खिलाफ चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमने पीएम मोदी को पूरा समर्थन दिया है। उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी को जो भी काम करना है, वह करना चाहिए।

परमाणु शक्ति होने के पाकिस्तान के बार-बार के दावों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने उन्हें भारत की अपनी क्षमताओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है और हमारे पास यह उनसे पहले भी थे। भारत के गैर-आक्रामक होने के रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। यह सब वहीं से शुरू हुआ और हमने जवाब दिया। आज भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक कि वे इसका इस्तेमाल न करें, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास भी हैं। ऊपर वाला ऐसी स्थिति कभी न आने दें।

कांग्रेस पार्टी द्वारा पीएम मोदी की आलोचना करने पर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने 28 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी को गायब बताने वाला पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया था। हालांकि, इस पोस्टर को बाद में डिलीट कर दिया गया। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के कथन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे कहां लापता है। मुझे पता है कि वह दिल्ली में है।

उन्होंने भारत की धरती पर बार-बार आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुंबई हमला हुआ और यह साबित हो गया कि उन्होंने इसे अंजाम दिया। पठानकोट और उरी हमला भी उन्होंने किया। उन्होंने कारगिल युद्ध किया और मैं उस समय मुख्यमंत्री था। अब्दुल्ला ने कहा कि वे इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन जब हमने कड़ी कार्रवाई की, तो वे मदद मांगने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भागे थे। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वे दोस्ती चाहते हैं, तो ऐसी चीजें जारी नहीं रह सकतीं। इसे रोकना होगा, लेकिन अगर वे दुश्मनी चाहते हैं, तो हम तैयार हैं।

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चीन और भारत की एक नीति पर पाकिस्तान का कोई इमान नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीएएन के मुताबिक, दुनिया के नौ देशों के पास कुल मिलाकर करीब 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये देश रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, भारत, इजरायल और उत्तर कोरिया हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार रूस के पास हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,224 हथियार हैं। जरुरी बात ये है कि अमेरिका ने अपने कई परमाणु हथियार इटली, तुर्किये, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी तैनात कर रखे हैं। लेकिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, वे इनके इस्तेमाल को लेकर बेहद गंभीर और जिम्मेदार रवैया रखते हैं। हर देश ने अपने-अपने स्तर पर परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर नियम और नीति बना रखी है। हालांकि पाकिस्तान को लेकर अक्सर आशंका रहती है, क्योंकि वहां के कई नेता और यहां तक कि संसद सदस्य भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं।

क्या है भारत और चीन की नीति

भारत और चीन दोनों ने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी-अपनी स्पष्ट नीतियां बना रही हैं। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज (एनएफयू) नीति की घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि वह कभी भी किसी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। रिपोर्ट बताती है कि भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने भी अपनी किताब में नीति का जक्रि करते हुए कहा था कि भारत की रणनीति न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की इस नीति का मकसद संदेश देना है कि वह परमाणु हथियारों का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए करेगा, वह भी तब जब उस पर परमाणु हमला हो जाए। वहीं चीन की नीति भी भारत की ही तरह है। 16 अक्टूबर 1964 को अपने पहले परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद, चीन ने ऐलान किया था की कि वह किसी भी वक्त और किसी भी हालात में परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। यह नीति 2025 तक आधिकारिक रूप से बरकरार है।

लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट और आधिकारिक नीति नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज (एनएफयू) नीति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। इसके उलट, पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज यानी पहले हमला करने को अपनी नीति का हिस्सा बना रखा है। इसके मायने ये है कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर किसी भी समय परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी थी उन्होंने कहा था कि हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत के लिए तैनात कर रखी हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717